

मौसम



अधिकतम तापमान 39.८

न्यूनतम तापमान 30.८

बाजार



सोना 101.700g

चांदी 106.000 kg

सत्य का स्वर

भारत संवाद

प्रयागराज, लखनऊ तथा मुम्बई से एक साथ प्रकाशित

संक्षिप्त समाचार
यूनेस्को की 40% साइटें पानी की कमी का कर रही सामना, ताजमहल का नाम भी शामिल

एक नए विश्लेषण से पता चलता है कि भारत सहित सभी गैर-समुद्री यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में से 73% कम से कम गंभीर जल जोखिम (जल तनाव, सूखा, नदी या तटीय बाढ़) से प्रस्त हैं, जिनमें से 21% को एक वर्ष बहुत अधिक पानी होने और दूसरे वर्ष बहुत कम पानी होने की दोहरी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। विश्व संसाधन संस्थान के एक्वाडक्ट डेटा (जो एक जल जोखिम एटलस भी है) पर आधारित विश्लेषण में कहा गया है कि भारत में गंभीर जोखिम वाले स्थलों में ताजमहल, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिमी घाट, महाबलीपुरम में स्मारक समूह और महान जीवित चोल मंदिर शामिल हैं। यूनेस्को की लगभग 40% साइटें जल तनाव और सूखे से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही हैं, और 33% और 4% नदी बाढ़ और तटीय बाढ़ के जोखिम का सामना कर रही हैं। पानी पृथ्वी के कुछ सबसे प्रिय स्थानों को प्रभावित कर रहा है। उदाहरण के लिए, ताजमहल को पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है जो पट्टण को बड़ा रहा है और भूजल को कम कर रहा है,

भारतीय रेलवे ने लॉन्च किया रेलवन ऐप, एक प्लेटफॉर्म पर मिलेगी रेल से जुड़ी सारी सेवाएं

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, जिसे यात्रियों को टिकट बुकिंग, ट्रेन और पीएनआर पूछताछ, यात्रा योजना, रेल सहायता और भोजन बुकिंग सहित कई सेवाओं तक सुविधाजनक पहुंच प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एंड्रॉइड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध इस ऐप का उद्घाटन सेंटर फोर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स (सीआरआईएस) के 40वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान किया गया। रेल मंत्रालय की एक प्रेस विज्ञप्ति में रेलवन ऐप को सभी यात्री जरूरतों के लिए एक व्यापक समाधान बताया गया।

इसने इस बात पर प्रकाश डाला कि उपयोगकर्ता आरक्षित और अनारक्षित टिकटिंग, प्लेटफॉर्म टिकट, ट्रेन और पीएनआर पूछताछ और भोजन बुकिंग जैसी विभिन्न सेवाओं तक सीधे ऐप के माध्यम से पहुँच सकेंगे। संचार में यह भी कहा गया है कि इसमें माल ढुलाई पूछताछ की सुविधाएँ भी शामिल हैं। मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि ऐप का प्राथमिक उद्देश्य सरल और सहज इंटरफेस के माध्यम से उपयोगकर्ताओं के अनुभव को बेहतर बनाना है। उन्होंने कहा कि ऐप न केवल सभी सेवाओं को एक स्थान पर एकीकृत करता है, बल्कि यह उन सेवाओं के बीच एकीकृत कनेक्टिविटी भी प्रदान करता है

वार गौरव भाटिया का आरजेडी पर वार

मौलाना तेजस्वी हमें बताइए कि क्या आपने कभी संविधान पढ़ा है?

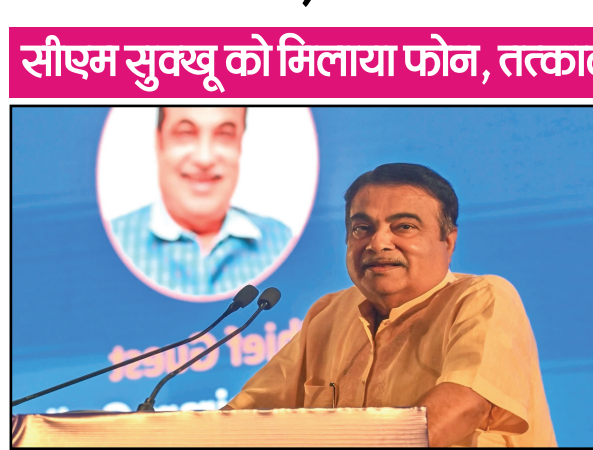
एजेंसी नई दिल्ली , भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजद नेता तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला और उन पर शरिया कानून को बढ़ावा देने और संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाया। भाटिया ने वक्फ संशोधन अधिनियम पर यादव की टिप्पणी की आलोचना की और उन पर और उनकी पार्टी पर संविधान का अनादर करने और सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। मीडिया को संबोधित करते हुए भाटिया ने कहा कि बिहार में जो लोग खुद को समाजवादी कहते हैं, वे असल में 'नमाजवादी' हैं। वे 'नमाजवादी' डॉ. बाबासाहेब



अंबेडकर के संविधान को नहीं चाहते। वे न तो उसका सम्मान करते हैं और न ही उसका पालन करते हैं। वे असल में शरिया कानून चाहते हैं। वे 'हलाल' जैसी प्रथाओं का समर्थन करते हैं और मानते हैं कि केवल एक विशेष धर्म को ही सशक्त बनाया जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि अगर कोई दलितों, महिलाओं और पिछड़े समुदायों को

सशक्त बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण का विरोध कर रहा है, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि यह राजद और तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी यादव द्वारा वक्फ संशोधन कानून को खारिज करने की कथित टिप्पणी का सीधा संदर्भ देते हुए भाटिया ने कहा, भाजपा संविधान की बात करेगी, जबकि आप शरिया को बढ़ावा देंगे।

पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जिस तरह से कहा कि भारतीय संसद द्वारा पारित कानून, वक्फ संशोधन कानून, वह उसे कूड़ेदान में डाल देंगे, यह दुःखद है। कृपया मुझे बताएं, क्या आपने कभी संविधान पढ़ा है? क्या आप संविधान के मूल नियमों को भी जानते हैं? एक कानून जो संसद में पारित होता है, संसद द्वारा अनुमोदित होता है, आप यह कैसे कह सकते हैं कि एक राज्य का नेता उसे कूड़ेदान में फेंक सकता है? उन्होंने कहा कि कल नवीं फेल पूर्व उप मुख्यमंत्री और नेता



प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे थे कि भारत की संसद से पारित वक्फ संशोधन कानून को कूड़ेदान में डाल देंगे। नमाजवादी और तुष्टिकरण के मसीहा मौलाना तेजस्वी यादव ये हमें बताइए कि क्या आपने कभी संविधान पढ़ा है, कभी उसकी मूल भावना को चरितार्थ किया है? उन्होंने कहा कि जंगलराज बिल्कुल लालू और तेजस्वी जैसा होता है। जंगलराज का पहला नियम है, संविधान और कानून की धज्जियां उधेड़ दी जाती हैं और वो ही काम विपक्ष में रहकर तेजस्वी यादव कर रहे हैं।

नई दिल्ली , केद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एनएचआई शिमला के प्रबंधक अचल जिंदल पर कथित हमले की शिमला में एनएचआई शिमला के प्रबंधक अचल जिंदल पर कथित हमले की



ऐप में पढ़ें

E-PAPER

भारत संवाद



Scan for E-Paper or Search on Play store Bharat Samvad E-Paper

राष्ट्रपति मुर्मू ने आयुष विश्वविद्यालय का किया लोकार्पण

कहा- पूरे विश्व में बज रहा भारत का डंका

उद्घाटन समारोह
मुर्मू ने इस विश्वविद्यालय के रोजगारपरक पाठ्यक्रमों और पारंपरिक विविधता पद्धतियों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर के शोध पर जोर देने की सराहना की। उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई देते हुए उन्होंने कहा, जनसेवा के लिए परिश्रम जरूरी है। जनसेवा में थकना नहीं चाहिए। उन्होंने विश्वविद्यालय से जुड़े लोगों से कहा, आपको बचने का अधिकार नहीं है।

एजेंसी गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को कहा कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है और यदि हम स्वस्थ रहेंगे, तभी 2047 तक विकसित भारत और विश्व गुरु बनने का सपना पूरा हो सकेगा। वह गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रही थीं। यह विश्वविद्यालय 268 करोड़ रुपये की लागत से बनकर तैयार हुआ है। राष्ट्रपति ने 21 जून को मनाए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा, योग को आज विश्व स्तर पर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसेवा और समर्पण की प्रशंसा करते हुए मुर्मू ने कहा, योगी जी और उनके मंत्रों जनता को हर सुविधा प्रदान करते हैं। इस विश्वविद्यालय के अधिकारियों, डॉक्टरों और नर्सों को भी निम्नजीत बनकर जनता की सेवा करनी होगी। महायोगी गुरु गोरखनाथ को नमन करते हुए उन्होंने कहा, मुझे बताया गया कि आदिशंकराचार्य के बाद गुरु गोरखनाथ जैसा प्रभावशाली व्यक्तित्व नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि गोरखपुर योग की भूमि है, जिसे गुरु गोरखनाथ ने आध्यात्मिक ऊर्जा से समृद्ध किया है।

मान्यता प्राप्त हुई है। शारीरिक श्रम करने वालों के लिए योग उतना जरूरी नहीं, लेकिन कार्यालयों में काम करने वालों के लिए यह बेहद आवश्यक है। उन्होंने भारत की समृद्ध परंपराओं का उल्लेख करते हुए कहा, हम अपने पूर्वजों, ऋषि-मुनियों की संतान हैं, इसलिए उनकी गरिमा को बनाए रखना हमारा दायित्व है। राष्ट्रपति ने कहा, आज भारत का गौरव विश्व भर में गूंज रहा है। इस गौरव को और बढ़ाने के लिए प्रत्येक भारतीय को स्वस्थ रहना होगा। यदि हम स्वस्थ रहेंगे, तभी 2047 तक विकसित भारत और विश्व



गुरु बनने का सपना साकार होगा। इसके लिए हमें अभी से प्रयास शुरू कर देने चाहिए। मुर्मू ने इस विश्वविद्यालय के रोजगारपरक पाठ्यक्रमों और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर के शोध पर जोर देने की सराहना की। उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय

देश में कहीं पर भी दर्ज हो एफआईआर, 3 साल में मिलकर रहेगा न्याय...

नए अपराधिक कानूनों पर बोले अमित शाह

एजेंसी केद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि तीन नए अपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आने वाले दिनों में अपराधिक न्याय प्रणाली को बदल देंगे। आज इन तीन नए अपराधिक कानूनों के एक वर्ष पूरे होने पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए शाह ने कहा कि इस प्रणाली के पूर्ण कार्यान्वयन में अधिकतम तीन वर्ष लगेंगे। उन्होंने कहा कि भारत की अपराधिक न्याय प्रणाली के सामने सबसे बड़ी समस्या न्याय प्राप्त करने के

देश के सबसे बड़े कर सुधारों में से एक, जीएसटी की शुरुआत ने भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एक सुव्यवस्थित कर संरचना में एकीकृत करने में मदद की।

भारत सरकार द्वारा हर साल 1 जुलाई को मनाया जाने वाला जीएसटी दिवस, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के औपचारिक रूप से लागू होने की आठवीं वर्षगांठ का प्रतीक है। देश के सबसे बड़े कर सुधारों में से एक, जीएसटी की शुरुआत ने भारत की अप्रत्यक्ष कर संरचना में एकीकृत करने में मदद की। जीएसटी के शुभारंभ के दिन का उपयोग जीएसटी ढांचे के बारे में जागरूकता और अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। हालांकि, यह बात भी सही है कि कांग्रेस लगातार इसका विरोध करती

जीएसटी के आठ साल पूरे, बोले राहुल गांधी

राहुल ने कहा कि भारत के सबसे बड़े रोजगार सृजक एमएसएमई को सबसे अधिक नुकसान हुआ है। आठ साल पहले जीएसटी लागू होने के बाद से 18 लाख से अधिक उद्यम बंद हो गए हैं। नागरिक अब वाय से लेकर स्वास्थ्य बीमा तक हर चीज पर जीएसटी का भुगतान करते हैं, जबकि कॉर्पोरेट सालाना 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक कर छूट का आनंद लेते हैं।

राहुल ने कहा कि भारत के सबसे बड़े रोजगार सृजक एमएसएमई को सबसे अधिक नुकसान हुआ है। आठ साल पहले जीएसटी लागू होने के बाद से 18 लाख से अधिक उद्यम बंद हो गए हैं। नागरिक अब वाय से लेकर स्वास्थ्य बीमा तक हर चीज पर जीएसटी का भुगतान करते हैं, जबकि कॉर्पोरेट सालाना 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक कर छूट का आनंद लेते हैं।

राहुल ने कहा कि भारत के सबसे बड़े रोजगार सृजक एमएसएमई को सबसे अधिक नुकसान हुआ है। आठ साल पहले जीएसटी लागू होने के बाद से 18 लाख से अधिक उद्यम बंद हो गए हैं। नागरिक अब वाय से लेकर स्वास्थ्य बीमा तक हर चीज पर जीएसटी का भुगतान करते हैं, जबकि कॉर्पोरेट सालाना 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक कर छूट का आनंद लेते हैं।

देश में कहीं पर भी दर्ज हो एफआईआर, 3 साल में मिलकर रहेगा न्याय...

नए अपराधिक कानूनों पर बोले अमित शाह

एजेंसी शाह ने कहा कि मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इसके बाद देश के किसी भी कोने में एफआईआर दर्ज करें, आपको 3 साल के भीतर न्याय मिलेगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा।

लिफ समयसीमा का अभाव है। शाह ने कहा कि मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इसके बाद देश के किसी भी कोने में एफआईआर दर्ज करें, आपको 3 साल के भीतर न्याय मिलेगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा। बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए ने क्रमशः औपनिवेशिक युग की भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली। नए कानून 1

मनोजीत कैपस में नजर आ जाए तो क्लास छोड़ने लगती थी छत्राएं

कोलकाता गैंगरेप के आरोपी पर होश उड़ाने वाला खुलासा

छात्रा ने कहा कि कैपस में डर का माहौल था। वह छात्राओं की तरकीबें खींचता था, उन्हें गॉफ करता था और उन्हें वॉट्सएप ग्रुप में प्रस्तावित करता था। उन्होंने कहा कि मिश्रा ने पहले भी महिला छात्राओं का यौन उत्पीड़न किया है और छात्राएं उनकी धमकी के कारण कक्षाओं में जाने से डरती हैं।

कोलकाता में 24 वर्षीय कानून की छात्रा के साथ बलात्कार के सिलसिले में गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद, उसी कॉलेज की एक अन्य छात्रा ने परिसर में मोनोजीत मिश्रा के डर के बारे में खुलासा किया है। मुख्य आरोपी मोनोजीत मिश्रा और दो अन्य

शिमला में एनएचआईआई मैनेजर पर हमला, गडकरी हुए नाराज

सीएम सुक्खू को मिलाया फोन, तत्काल कार्रवाई की मांग

गडकरी ने हमले को जघन्य और गंभीर रूप से निंदनीय बताते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से त्वरित और अनुकरणीय कार्रवाई की मांग की है।

रूप से निंदनीय बताते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से त्वरित और अनुकरणीय कार्रवाई की मांग की है। केद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक्स पर लिखा कि एनएचआईआई पीआईयू शिमला के प्रबंधक अचल जिंदल पर हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज मंत्री और उनके सहयोगियों द्वारा किया गया जघन्य हमला अत्यंत निंदनीय है और कानून के शासन का अपमान है।

सम्पादकीय

कोलकाता लॉ कॉलेज में दुष्कर्म, पश्चिम

बंगाल सरकार को शर्मसार करने वाली घटना

विडंबना यह है कि महिलाओं के संदर्भ में समाज की मानसिकता बदलने का काम राजनीतिक दलों के एजेंडे से करीब-करीब बाहर है। दुष्कर्म की घटनाओं पर राजनीतिक दल आरोप-प्रत्यारोप में तो उलझ जाते हैं लेकिन इस पर ध्यान नहीं देते कि वे अपने कैडर एवं समर्थकों को महिला सुरक्षा के संदर्भ में कोई सही संदेश दे पा रहे हैं या नहीं? कम से कम अब तो सभी दल ऐसा करें। पहले मेडिकल कालेज में डाक्टर के साथ और अब ला कालेज में छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना पश्चिम बंगाल सरकार को शर्मसार करने वाली ही है। चिंताजनक यह है कि ये दोनों घटनाएं एक वर्ष के अंदर कोलकाता के उन परिसरों में हुईं, हुईं जहां इसकी न्यूनतम आशंका होती है। यह तथ्य कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है कि देश को चिंतित करने वाली दोनों घटनाएं बंगाल की राजधानी कोलकाता में हुईं। यह ठीक है कि ला कालेज में सामूहिक दुष्कर्म की घटना पर कोलकाता पुलिस ने तत्परता दिखाई, लेकिन यह दुर्घटना नहीं हो सकती कि दोनों घटनाओं में तृणमूल कांग्रेस से जुड़े लोग सामने आए। मेडिकल कालेज की घटना पर तो तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने लीपापोती करने की भी कोशिश की थी। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि ला कालेज की घटना पर ममता सरकार गंभीर नजर आ रही है, क्योंकि अभियुक्तों पर निगाह डालने से यही स्पष्ट होता है कि तृणमूल कांग्रेस में अराजक तत्व शरण पा रहे हैं। इसे इंगित करने वाली घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। ममता बनर्जी सरकार में बहुत कुछ वैसा ही रहा है, जैसा कभी वाम दलों की सरकारों के समय हुआ करता था। ला कालेज की घटना इसलिए कहीं अधिक गंभीर है, क्योंकि छात्रा के साथ दुष्कर्म गांड रूम में हुआ और घटना में कालेज के कुछ छात्र लिप्त पाए गए। इस घटना पर तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेताओं ने बेहद शर्मनाक बयान दिए। इसका कोई मतलब नहीं कि पार्टी ने अपने नेताओं के अपमानजनक बयानों पर नाजायगी प्रकट की और संबंधित विधायक एवं सांसद की खिंचाई की। इससे उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। वे पहले भी अभद्र बयान देते रहे हैं। जब राजनीति में ऐसे लोग होंगे, तो वे समाज पर घातक असर डालेंगे ही। यह सोचा जा रहा था कि दुष्कर्म संबंधी कानून कठोर करने के बाद दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म की घटनाएं थमेगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। कई राज्यों में किशोरियों के साथ दुष्कर्म की घटनाओं के दोषियों को मृत्युदंड देने के प्रविधान किए गए हैं, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात वाला है। दुष्कर्म की घटनाएं कानून एवं व्यवस्था पर ही सवाल नहीं उठातीं, बल्कि समाज की मानसिकता को भी बयान करती हैं। विडंबना यह है कि महिलाओं के संदर्भ में समाज की मानसिकता बदलने का काम राजनीतिक दलों के एजेंडे से करीब-करीब बाहर है।

आज का विचार

हारने से कभी मत डरना, क्योंकि हार जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है या तो जीत मिलती है सीख

भारत संवाद



मेघ राशि : करियर: माता-पिता के आशीर्वाद से आज काम में अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपके व्यवहार और काम का सकारात्मक असर दूसरों पर पड़ेगा। बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो बिजनेस से जुड़े अनुभवी लोगों से सलाह जरूर लें।

वृषभ राशि: करियर: आज दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। नौकरी में स्थिति सामान्य रहेगी, धैर्य बनाकर कुछ व्यवसायिक गतिविधियां थोड़ी धीमी रहेंगी, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए संयम ही उचित रहेगा

मिथुन राशि : करियर: नई नौकरी के योग बन रहे हैं। किसी उलझन का समाधान होगा जिससे मन हल्का रहेगा। आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान दें. खर्चों को सीमित रखें और अनावश्यक मामलों में हस्तक्षेप से धन: किसी दोस्त की आर्थिक मदद करनी पड़ सकती है. लेन-देन में सावधानी रखें.

कर्क राशि: करियर: दिनचर्या व्यवस्थित रखने से कार्य समय पर पूरे होंगे. काम पर ध्यान देना भविष्य में फायदेमंद रहेगा बिजनेस: बिजनेसमैन किसी कंपनी के साथ साझेदारी कर सकते हैं. नई योजनाओं पर काम शुरू होगा. धन: वित्तीय मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें.

सिंह राशि: करियर: वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा. ऑफिस में प्रेजेन्टेशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है. बिजनेस: नया कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है. राजनीतिक संबंध भी लाभदायक हैं. शिक्षा: छात्रों के लिए मिल सकते हैं.

कन्या राशि: करियर: ऑफिस में काम का दबाव रहेगा. सहयोगियों से तालमेल बनाए रखें बिजनेस: व्यावसायिक सफलता से माता-पिता प्रसन्न होंगे. फिजूलखर्ची से बचें. अपनी जरूरतों को प्राथमिकता दें. प्रोजेक्ट पूरा करने में भाई-बहन

या टीचर की मदद लें.

तुला राशि: करियर: दिन तरक्की देने वाला रहेगा. कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी. बिजनेस: अटका पैसा वापस मिलने की संभावना है. धन: सुख-सुविधा की वस्तुओं की खरीदारी में खर्च होगा.

वृश्चिक राशि: करियर: काम समय पर पूरे होंगे. समाज में आपकी छवि सुधरेगी. आज व्यवसाय में लाभ की स्थिति बन सकती है. परिवार पर धन खर्च होगा शिक्षकों का दिन व्यस्त रहेगा.

धनु राशि : करियर: जीवनसाथी के साथ बाहर जाने का मौका मिलेगा. किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन लाभ देगा. बिजनेस: कोई नई योजना शुरू हो सकती है. धन: रुकी हुई आर्थिक समस्या सुलझ सकती है.

मकर राशि: करियर: परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी. सकारात्मक सोच से काम सफल होंगे. बिजनेस: प्रॉपर्टी डीलिंग से लाभ मिल सकता है. धन: धन के मामलों में सजग रहें.

कुंभ राशि: करियर: अतिरिक्त जिम्मेदारियां पूरी होंगी. समाज में पहचान बढ़ेगी. फैशन डिजाइनिंग से लाभ हो सकता है. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा.

मीन राशि : करियर: कार्यक्षेत्र में तालमेल अच्छा रहेगा. मार्केटिंग में सफलता मिलेगी. बिजनेस: बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए विशेषज्ञ की सलाह लें. धन: धन से जुड़ा मामला सुलझ सकता है. शिक्षा: छात्रों के लिए दिन अच्छा रहेगा. लव/पारिवारिक: लवमेट के लिए दिन शानदार रहेगा. जीवनसाथी से भावनात्मक सहयोग मिलेगा. उपाय: मछलियों को आटा खिलाएं.

ज्योतिष सेवा केन्द्र
ज्योतिषाचार्य पंडित अतुल शास्त्री

हिंदी विरोध की खतरनाक राजनीति: राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सामाजिक सद्भाव पर भारी

महाराष्ट्र में हिंदी विरोध के मूल में सस्ती राजनीति ही है। अपने मुद्दों की नाकामी से जनाधार गंवा चुके राजनीतिक दलों और नेताओं को लगता है कि मराठी अस्मिता के जांचे-परखे पुराने दांव से शायद भविष्य में उनकी चुनावी नैया पार लग जाएगी लेकिन संकीर्ण राजनीतिक लाभ के लिए वे जो कीमत चुकाने पर आमादा हैं वह राष्ट्रीय एकता अखंडता और सामाजिक सौहार्द पर भारी पड़ सकती है।

पा दक्षिण भारत में अक्सर राजनीतिक हित साधने के लिए हिंदी विरोध को एक कारगर हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता रहा है। अब लगता है कि महाराष्ट्र की बारी है। जिन अहिंदी भाषी राज्यों में भी हिंदी बोलने-समझने वाले ही नहीं, हिंदी लिखनेवाले भी बड़ी संख्या में मिल जाते हैं, उनमें महाराष्ट्र अग्रणी है। मूलतः मराठीभाषी हिंदी साहित्यकारों और पत्रकारों की संख्या भी कम नहीं है। जिस हिंदी सिनेमा की हिंदी भाषा के प्रसार में बड़ी भूमिका की बात कही जाती है, उसका केंद्र महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई ही है। मराठी मूल के असंख्य लोगों ने फिल्म निर्माण से लेकर अभिनय तक, हिंदी सिनेमा में बड़ा नाम कमाया है। दादा साहेब फाल्के को भारतीय फिल्म उद्योग का पितामह कहा जाता है। देश का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म सम्मान ह्यादादा साहेब फाल्के अवार्ड उन्हीं की स्मृति में दिया जाता है। क्या वी. शांताराम के बिना हिंदी सिनेमा की कहानी कही जा सकती है? यह फेहरिस्त बहुत लंबी बन सकती है। महाराष्ट्र में अब त्रिभाषा फामूलें के अंतर्गत स्कूलों में हिंदी पढ़ाए जाने के फैसले को हिंदी थोपना बता कर बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। नई शिक्षा नीति, 2020 के अनुसार देश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में तीन भाषाएं पढ़ाई जाएंगी, जिनमें से दो



भारतीय और तीसरी विदेशी होगी। नई शिक्षा नीति के अनुरूप ही त्रिभाषा फामूलें को लागू करते हुए महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में पहली से पांचवीं कक्षा तक मराठी, हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाए जाने का फैसला लिया। इसका खासकर शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना द्वारा जोरदार विरोध शुरू हो गया संकीर्ण राजनीति प्रेरित अतार्किक विरोध के आगे झुकते हुए महायुति सरकार ने अपने आदेश में संशोधन भी कर दिया कि विद्यार्थी मराठी और अंग्रेजी के साथ तीसरी भाषा के रूप में हिंदी के बजाय कोई अन्य भारतीय भाषा भी चुन सकते हैं। इसके बावजूद महाराष्ट्र में हिंदी विरोध थमता नहीं दिख रहा। उद्धव की शिवसेना और राज की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अब मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में हिंदी पढ़ाए जाने के विरोध में संयुक्त विरोध प्रदर्शन करने जा रही हैं। अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस पाने के लिए उद्धव और राज ठाकरे की तरह शरद पवार भी मराठी अस्मिता के भावनात्मक मुद्दे को भुनाने का मौका नहीं चूकना चाहते। हिंदी विरोधी प्रदर्शन को उन्होंने भी समर्थन का एलान कर दिया है। ऐसा ही दबाव अन्य विपक्षी दलों पर भी नजर आ रहा है, क्योंकि ऐसे भावनात्मक मुद्दे हमारी चुनावी राजनीति में वास्तविक मुद्दों पर भारी पड़ते रहे हैं। मुख्यमंत्री फडणवीस ने आरोप लगाया है कि अपने मुख्यमंत्रित्वकाल में नई शिक्षा नीति को मंजूरी देने वाले उद्धव ठाकरे बीएमसी समेत आगामी नगर निगम चुनावों में राजनीतिक लाभ के लिए ही हिंदी विरोध को हवा दे रहे हैं। सच यह भी है कि बाला साहब ठाकरे द्वारा गठित शिवसेना की पहचान शुरू में हिंदी भाषा तथा गैर मराठी प्रवासियों के विरोधी की ही रही। मराठी अस्मिता के नाम पर ही

शिवसेना ने महाराष्ट्र में अपने पैर पसारे, लेकिन पहले भाजपा से गठबंधन और फिर उससे तकरार के बाद कांग्रेस-राकांपा के साथ महा विकास अघाड़ी सरकार बनाने से वह पहचान धूमिल होती गई। अब जबकि राज ठाकरे के साथ ही उद्धव ठाकरे के समक्ष भी राजनीतिक भविष्य का संकट खड़ा हो गया है, तब दोनों मिलकर हिंदी विरोध के जरिये मराठी अस्मिता के मुद्दे को धार दे कर पुनरुत्थान की कोशिश कर रहे हैं। पिछले साल विधानसभा चुनाव के बाद दोनों ठाकरे भाइयों में एकता की चर्चाएं लगातार चलती रही हैं। हिंदी विरोध के रूप में उन्हें मनचाहा मुद्दा भी मिल गया है। बदलते सामाजिक-आर्थिक परिवेश में भाषाई संकीर्णता का यह मुद्दा कितना कारगर होगा, इसकी पहली परीक्षा बृहद मुंबई महापालिका यानी बीएमसी समेत कुछ नगर निगमों के निकट भविष्य में होनेवाले चुनावों में होगी। बीएमसी पर सभी दलों की नजर इसलिए भी रहती है कि उसका बजट देश के कई राज्यों से बड़ा है। आम धारणा है कि बीएमसी पर काबिज दल के लिए महाराष्ट्र में राजनीति करना आसान हो जाता है। महाराष्ट्र में हिंदी विरोध के मूल में सस्ती राजनीति ही है। अपने मुद्दों की नाकामी से जनाधार गंवा चुके राजनीतिक दलों और नेताओं को लगता है कि मराठी अस्मिता के जांचे-परखे पुराने दांव से शायद भविष्य में उनकी चुनावी नैया पार लग जाएगी, लेकिन संकीर्ण राजनीतिक लाभ के लिए वे जो कीमत चुकाने पर आमादा हैं, वह राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सामाजिक सौहार्द पर भारी पड़ सकती है। ऐसे में महाराष्ट्र के जागरूक नागरिकों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। जन साधारण को समझाना होगा कि नई शिक्षा नीति के अनुरूप पहली से पांचवीं कक्षा तक हिंदी पढ़ाए जाने को हिंदी थोपना बता कर विरोध कर रहे राजनीतिक दलों और नेताओं ने राज्य में कभी अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों का विरोध नहीं किया। बेशक वैश्विक गांव की परिकल्पना के इस दौर में किसी विदेशी भाषा का विरोध भी समझदारी नहीं, पर एक ही विशाल भाषा परिवार की सदस्य भारतीय भाषाओं को एक-दूसरे के मुकाबले खड़ा करने की साजिश तो देश के प्रति अक्षम्य अपराध है।

प्रकृति का रौद्र रूप कहीं बाढ़ कहीं भूस्खलन

संजीव ठाकुर

भारत में वषाकाल में भीषण प्राकृतिक वर्षा के फलस्वरूप बाढ़ भूस्खलन और नदियों में उफान आने से उत्तरांचल ,उत्तराखंड, असम, मेघालय, दिल्ली और पंजाब भीषण त्रासदी झेल रहे हैं और बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु भी हो गई है देश के साथ एकसाथ विश्व में कई देशों में अतिवृष्टि से बाढ़ का प्रकोप होता है लैंडस्लाइडिंग भी होती है पर सर्वाधिक मृत्यु भारत में ही होती है। भारत में भूकंप के झटके भी लगते हैं कई बार भूकंप भी आता है और जान माल की हानि होती है।यह ऐसा तो है नहीं कि अति वर्षा कई सालों में एक बार होती हो, वर्षा, बाढ़ तथा लैंडस्लाइडिंग का प्रकोप हर वर्ष अखबारों में हम पढ़ते हैं और लोगों की मृत्यु होती है तो ऐसे में केंद्र तथा राज्य सरकारों को आपस में सामंजस्य कर इस त्रासदी तथा विपदा का पहले से प्रबंध करने की आवश्यकता होनी चाहिए जिससे आमजन को जान माल का कम से कम नुकसान हो सके। आपदा सदैव अनअपेक्षित घटना होती है। जो मानवीय नियंत्रण से बाहर तथा प्राकृतिक व मानवीय कारकों द्वारा मूर्त रूप दी जाती है। प्राकृतिक आपदा अल्प समय में बिना किसी पूर्व सूचना के घटित होती है, जिससे मानव जीवन के सारे क्रियाकलाप अवरुद्ध हो कर, जान और माल की बड़ी हानि होती है। आपदा की गहनता, विशालता एवं निरंतरता मानव जीवन तथा समाज, देश को बड़ी हानि पहुंचाते हैं, एवं उस देश की आर्थिक स्थिति में गहरी चोट देते हैं। इन प्राकृतिक आपदाओं से सबसे ज्यादा खतरा बना रहता है। आपदा के समय सबसे ज्यादा निम्न आय वर्ग का व्यक्ति तथा मजदूर तबके का व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रभावित होकर उसकी दिनचर्या समूह रूप से छिन्न-भिन्न हो जाती है, एवं आर्थिक साधन की नष्ट हो जाते हैं, जिससे उसे आजीविका का एक बड़ा भार सताने लगता है। भारत के भू भाग का लगभग 58% क्षेत्र भूकंप की संभावना



भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी जैसी प्राकृतिक आपदाएं सदैव आती रहती हैं। जापान में आपदा प्रबंधन की अत्याधुनिक तकनीक को याकोहामा रणनीति कहा जाता है। जापान में आपदा प्रबंधन की साल भर नियमित रूप से मानिट्रिंग कर एक्ससाइज की जाती रहती है, एवं आपदाओं पर निरंतर निगरानी तथा नजर रखी जाती है, एवं इसके निदान के लिए पूर्व से ही सुनियोजित योजना बनाकर नागरिकों को सुरक्षित कर लिया जाता है। भारत को भी इसी तरह आपदा प्रबंधन को अपनाकर हमें बाढ़, अतिवृष्टि, लैंडस्लाइडिंग तथा भूकंप से पूरी क्षमता कथा विशेषताओं के साथ सामना करना चाहिए।

आपदाओं के प्रति मानवीय सभ्यता के संदर्भ में समाज के आर्थिक सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग को ज्यादा प्रभावित करती है। एवं समाज का सबसे संवेदनशील तबका यानी वृद्ध व्यक्ति, महिलाएं, बच्चों, दिव्यांग लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से सबसे ज्यादा खतरा बना रहता है। आपदा के समय सबसे ज्यादा निम्न आय वर्ग का व्यक्ति तथा मजदूर तबके का व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रभावित होकर उसकी दिनचर्या समूह रूप से छिन्न-भिन्न हो जाती है, एवं आर्थिक साधन की नष्ट हो जाते हैं, जिससे उसे आजीविका का एक बड़ा भार सताने लगता है। भारत के भू भाग का लगभग 58% क्षेत्र भूकंप की संभावना

वाला क्षेत्र है, जिसमें हिमालयिन क्षेत्र, पूर्वोत्तर राज्य, गुजरात का कुछ क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भूकंप की दृष्टि से सबसे सक्रीय क्षेत्र रहें है। देश के 65 से 68% भूभाग पर कभी कम कभी ज्यादा भीषण रूप से सूखा पड़ता है, इसी तरह भारत के पश्चिमी और प्रायद्वीपीय राज्य में मुख्यतः शुष्क तथा अर्ध शुष्क न्यून नमी वाले क्षेत्र सूखे से सदैव प्रभावित रहते हैं। बाढ़ से प्रभावित भूमि का विस्तार क्षेत्र देश के 12% है, यानी 7 करोड़ हेक्टेयर जमीन में भूकंप आने की संभावना सदैव बनी रहती है। हिमालय क्षेत्र देश के पर्वतीय क्षेत्र में भूस्खलन की गंभीर समस्या की संभावना सदैव बनी रहती है। देश के विशाल तटवर्ती क्षेत्र में चक्रवात तथा सुनामी की भयावह स्थिति की संभावना सदैव बनी रहती है।अब भारत में विश्व के साथ-साथ कोरोना संक्रमण की भयानक महामारी से प्रभावित होकर हजारों लाखों नागरिकों की जान गवा कर इस आपदा से जंग लड़ रहा है, यह कोविड-19 की महामारी या आपदा प्राकृतिक है या मानव निर्मित यह तो भविष्य ही बताएगा, किंतु इस महामारी ने पूरे वैश्विक स्तर पर आकस्मिक रूप से मानव जीवन में मृत्यु का तांडव मचा के रख दिया है। ऐसी ही अनपेक्षित आपदाओं का पूर्वानुमान अथवा आकलन किया जाना पहले से संभव नहीं हो सकता है। ऐसे में राष्ट्रीय अन्य

योजनाओं के साथ-साथ आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अत्यधिक सावधानी पूर्वक योजना तथा विभाग बनाने चाहिए, देश में जापान जैसे देश की तरह आपदा प्रबंधन से निपटने के लिए अत्याधुनिक आपदा प्रबंधन सिस्टम को तैनात कर तैयार रखने की आवश्यकता होगी। भारत को आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विभाग को चुस्त-दुरुस्त तथा अत्याधुनिक तकनीक से युक्त रखने की आवश्यकता है। तूफानी चक्रवात, सुनामी, भूस्खलन, भूकंप, सूखा बाढ़ के अलावा अब कोविड-19 यानी कोरोना संक्रमण जैसी खतरनाक बीमारियां भारत देश को अपना निशाना बना कर रखा है ऐसे में भारत में मध्यम दर्जे का या निम्न दर्जे का आपदा प्रबंधन सिस्टम किसी भी काम का ना रहेगा, एवं इससे भारी जानमाल की हानि होने की संभावना सदैव बनी रहेगी। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए 1990 में कृषि मंत्रालय के अंतर्गत डिजास्टर मैनेजमेंट सेल स्थापित किया गया था। लेकिन 1993 में लातूर के भूकंप तथा 1998 में मालया के भूस्खलन तथा 1999 में ओडिशा में सुपर साइक्लोन तथा 2001 में भुज के भूकंप के बाद देश में एक मजबूत आपदा प्रबंधन की व्यवस्था की जरूरत को महसूस करते हुए जे.सी. पंत जी की अध्यक्षता में हाई पावर कमिटी की रिपोर्ट में एक सुव्यवस्थित तथा व्यापक सिस्टम तथा विभाग की स्थापना की आवश्यकता प्रतिवेदित की गई थी। 2002 में आपदा को देश की आंतरिक सुरक्षा का मामला मानते हुए आपदा को गृह मंत्रालय के अंतर्गत समाविष्ट किया गया। आपदा प्रबंधन के इतिहास में 2005 में एक बड़ा परिवर्तन लाया गया भारत सरकार ने आपदा को अपनी कार्ययोजना के एक चक्रीय क्रम के रूप में प्रबंधित किया, जिसमें आपदा आ जाने के बाद इसके बचाव, नुकसान की भरपाई, निदान तथा आपदा आने के पूर्व की तैयारी तथा योजना को मूर्त रूप देने का एक सुनियोजित तरीका तैयार किया गया था।

मिश्रित शिक्षा: शैक्षिक परिवर्तन ड्राइविंग

विजय गर्ग

हम शिक्षा के एक युग में रह रहे हैं जो छात्रों और कामकाजी पेशवरों के लिए सक्षम परिस्थितियों का निर्माण कर रहा है, और जिसमें मिश्रित शिक्षण एक प्रमुख गेम-चेंजर होगा। भारत के भीतर, भारत की राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 2020 का कार्यान्वयन भारत में शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को नया रूप देने जा रहा है। एनईपी 2020 की दृष्टि एसडीजी 4 के साथ गठबंधन की गई भारतीय शिक्षा प्रणाली को फिर से कल्पना करना है, जो समान अवसर, समावेश और इक्विटी पर केंद्रित है। मिश्रित शिक्षण-शिक्षण वातावरण, क्निएटिव कॉमन्स और बड़े पैमाने पर ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम के तहत ओपन एजुकेशनल रिसोर्स क्षेत्रों और सामाजिक-आर्थिक स्तर पर एक प्रत्यक्ष विश्वविद्यालय नामांकन तक तंत्र बनाने के लिए आवश्यक आवश्यकताएं हैं। मेरे डॉक्टरेट थोसिस की रक्षा के दौरान धारणा को जानने के लिए छात्रों, संकाय सदस्यों और पुस्तकालय पेशेवरों सहित शैक्षणिक समुदायों के बीच एक ऑनलाइन सर्वेक्षण किया गया है। सर्वेक्षण में अपरंपरागत सीखने के अवसरों और संसाधनों के बारे में छात्रों और संकाय सदस्यों के बीच जागरूकता का एक निम्न स्तर सामने आया जो ऑनलाइन पाठ्यक्रमों जैसे आईटी बुनियादी ढांचे का लाभ उठाते हैं जो नवीनतम तकनीकी कौशल वृद्धि पाठ्यक्रमों में बड़ी संख्या में छात्रों तक पहुंच प्रदान करते हैं। उत्साहजनक और कुछ हद तक, संकाय सदस्यों ने सर्वेक्षण किया, छात्रों या यहां तक ​​​​कि पुस्तकालय पेशेवरों के सापेक्ष इन मामलों के बारे में उच्च जागरूकता प्रदर्शित की। इसने इस बात पर जोर दिया कि जब संकाय सदस्य ओईआर शैक्षिक संसाधनों को पारंपरिक कक्षा सेंट्रिस् में शामिल करते हैं, तो ओईआर संसाधनों की गुणवत्ता में सुधार होता है, इसलिए ऑनलाइन शिक्षा की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाता है। विभिन्न हितधारकों को पुस्तकालय प्रबंधन प्रणाली (एलएमएस) के साथ

ओईआर को एकीकृत करने और भारत में एचईआई में एक मजबूत ओईआर नीति ढांचा होने का दृष्टिकोण पाया गया। एलएमएस के साथ ओईआरएस को एकीकृत करने का दिश में हितधारकों के अनुकूल विचारों को शैक्षणिक समुदाय को ओपन-एक्सेस लाइसेंस और मिश्रित शिक्षण वातावरण की संस्कृति की बेहतर समझ हासिल करने में सक्षम बनाना चाहिए। इसलिए यह विशेष रूप से पेरी-शहरी आबादी और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले वंचित समुदायों के बीच मिश्रित शिक्षण शिक्षा को गति देने का अवसर है। 'ऑल इंडियन सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2021-22' के अनुसार, बिहार और असम में दूरस्थ नामांकन मोड उच्च जनसंख्या वृद्धि के बावजूद सबसे कम से से एक है और लोग उच्च शिक्षा के लिए उत्सुक हैं और राज के भीतर प्रत्यक्ष विश्वविद्यालय नामांकन तक बहुत कम पहुंच है। यह जलवायु साक्षरता और जलवायु शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। उच्च शैक्षिक संस्थानों द्वारा उद्घाटन का वास्तविक गोद लेना विभिन्न कारकों जैसे - समय और लागत, भाषा, उपयोगकर्ता-मित्रता, बुनियादी ढांचा, गुणवत्ता और पुस्तकालय समर्थन पर निर्भर करता है। शैक्षणिक प्रथाओं का विकास ओपन एजुकेशनल रिसोर्स (ओईआरएस) के बारे में जागरूकता से जुड़ा हुआ है, जो इन-पर्सन कक्षाओं के दौरान पारंपरिक शिक्षण विधियों में ओईआर सामग्री के एकीकरण की सुविधा प्रदान करता है। इसके अलावा, सरकारी सहायता उच्च शिक्षा संस्थानों में ओईआरएस के उपयोग और उन्नति को बढ़ाएगी और उच्च गुणवत्ता वाले खुले शैक्षिक संसाधनों के माध्यम से सूचना-समृद्ध और सूचना-गरीब संस्थाओं के बीच असमानताओं को कम करने की सुविधा प्रदान करेगी, जो सतत विकास लक्ष्य के उद्देश्य में से एक के साथ संरेखित होगी। एनईपी 2020 का उद्देश्य छात्रों, शिक्षार्थियों को एक साथ दो डिग्री हासिल करने की अनुमति देकर विविध कौशल विकसित करने के लिए सशक्त बनाना है।

कथा करने कराने से नहीं होता उद्धार, सत कर्म करते रहने से होगा वेडा पार - व्यास देव जी महाराज बृजवासी

बहादुर सिंह संवादाता गोड़ा /भारत संवाद

अलीगढ़। गौँडा क्षेत्र के गाँव रजावल में चल रही श्रीमद्भागवत कथा का आज आखिरी दिन व्यास देव जी महाराज त्रिज वासी ने कहा कि कथा भागवत करने व कराने से मानव का उद्धार नहीं होता, रामायण व गीता पढ़ने से मोक्ष प्राप्त नहीं होता जब तक मानव अपने आचरण, विचार, गीता रामायण के बताये



नियमों का पालन नहीं करेगा व उनके अनुसार नहीं चलेगा तब तक पूजा पाठ, कथा करना कराना व्यर्थ का है। व्यास जी ने बताया मोह, माया, लोभ, क्रोध व मध छोड़ कर जो ईश्वर की भक्ति करेगा किसी का बुरा न करना, अपनी आत्माओं को परमात्मा में लगा कर भक्ति करेगा मानव का

तभी उद्धार होगा। इसी के साथ श्री कृष्ण भगवान के वालसखा सुदामा की मित्रता का वितार से वर्णन करते हुए मानव के जीवन उद्धार के लिए विस्तार से वर्णन किया। आज की कथा में परीक्षत की भूमिका में अमित चौधरी, सूरज चौधरी, सभी चौधरी परिवार रहा परिवार की ओर से कथा वाचक व्यास देव जी महाराज का इक्कीस हजार रुपए भेंट कर फूलमाला पहनाकर स्वागत सम्मान किया कथा के विषयम उपरांत सभी भक्त जनों को कथा का प्रसाद वितरण किया गया।

जल मराव क्षेत्र का नगर आयुक्त ने किया निरीक्षण,जल निकासी के लिए अतिरिक्त पंप सेटों को लगाने के दिए निर्देश

चरकवालान पम्पिंग स्टेशन की बढेगी क्षमता

डोली शर्मा संवादाता महानगर/ भारत संवाद

अलीगढ़। बीती रात से लगातार हो रही बारिश की वजह से शहर के रामघाट रोड, छर्छा अड्डा,गुलर रोड, शाह जमाल,मैरिस रोड,ईदगाह रोड,खैर रोड पर हूए जल भराव का नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने निरीक्षण किया नगर आयुक्त ने गुलर रोड पंपिंग स्टेशन और गुलर रोड पोखर का भी निरीक्षण किया और इस निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त ने गुलर रोड पोखर के इनलेट चेम्बर की क्षमता को बढ़ाने व इसके डिजाइन को चेंज करने के निर्देश दिए इतना ही नहीं गुलर रोड पंपिंग स्टेशन पर जो पंप सेट लगे हैं उनके स्थान पर मड पंप लगवाए जाने व उनकी क्षमता में वृद्धि करने के निर्देश दिए नगर आयुक्त ने गुलर रोड पम्पिंग स्टेशन पर लगे डिलीवरी हैडर जिसकी क्षमता काफी छोटी थी उसको बदलने के निर्देश दिए।अब शाहजमाल ईदगाह में जल निकासी को प्रभावी बनाने के दृष्टिगत चरखवालान पंपिंग स्टेशन को अधिकतम क्षमता का बनाने का प्रस्ताव



तत्काल तैयार कराए जाने के निर्देश महाप्रबंधक जल को दिए गए।खैर रोड पर नाले में फ्लोटिंग मटेरियल गाए जाने पर नगर आयुक्त ने सफाई निरीक्षक अनिल सिंह का स्पष्टीकरण मांगे जाने के निर्देश दिए इसके अलावा उन्होंने खैर रोड पर जल निकासी को प्रभावी बनाने के दृष्टिगत जल निकासी में बाधक अतिक्रमण को नगर निगम राजस्व टीम से चिह्नित कराते हुए उन्हें प्राथमिकता पर हटवाये जाने की कार्रवाई करने के निर्देश सहायक नगर आयुक्त वीर सिंह को दिए।खैर रोड पर जल भराव को देखने पहुंचे नगर आयुक्त ने स्थानीय लोगों से बातचीत की और उन्हें पूरा भरोसा दिलाया जल

जीआईएस सर्वे को लेकर व्यापारियों की अहम बैठक

जीआईएस सर्वे से हो रहा जनता का उत्पीड़न: विवेक मनोचा

भारत संवाद



उसको नहीं रोका। जिससे व्यापारियों में इस बात का भारी रोष है।

जबकि आज 30 जून को गाजियाबाद नगर निगम बोर्ड ने वहां की महापौर सुनीता दयाल की अध्यक्षता में जिस जीआईएस सर्वे को दो माह के लिए स्थगित कर दिया और वहां के अधिकारियों को ईडी नीति बनाने के लिए आदेशित किया।

महानगर महामंत्री पुनीत चैहान एवं कोषाध्यक्ष सुधीर मिंगलानी ने कहा यदि गाजियाबाद नगर निगम जनता के हित में यह निर्णय ले सकता है तो क्या

सहारनपुर में कोई नई तरह के कानून लागू होते हैं ? इसलिए यदि यहां के नेताओं ने तुरंत कोई जनहित में निर्णय नहीं लिया तो अगले बड़े आंदोलन की तैयारी हो चुकी है बैठक में प्रांतीय उपाध्यक्ष यशपाल मैनी, प्रांतीय संगठन मंत्री अशोक छाबड़ा, प्रांतीय संगठन मंत्री आरके मल्होत्रा, प्रांतीय मंत्री महेश नारंग, प्रांतीय मंत्री अमित, व्यापार मंडल के युवा व्यापार मंडल के अध्यक्ष अनुभव शर्मा महामंत्री कुबेर नरुल्ला, कोषाध्यक्ष विनीत चैहान सहित कोर कमटी के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

वार्ड 59 में सड़क निर्माण के विवाद को नगर आयुक्त ने पहुँचकर सुलझाया-पार्षद संग नगर आयुक्त ने किया निरीक्षण

जमालपुर बड़े नाले के दोनों साइड अतिक्रमण की जल्द होगी पैमाइश-जमालपुर नाले की सड़क का होगा चौड़ीकरण

○ खैर रोड जल निकासी के लिए कल टूटेंगे अवैध स्लैब, रैप अतिक्रमण-नगर निगम 2 जुलाई को सुबह 10 बजे अतिक्रमण हटाने की करेगा कार्यवाई

भारत संवाद

जमालपुर के वार्ड 59 में सड़क निर्माण के विवाद के कारण लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने पार्षद असलम नूर के साथ जमालपुर बड़ी मस्जिद वाली गली में सड़क निर्माण के विवाद को मौके पर जाकर देखा। स्थानीय लोगों से विवादित सड़क निर्माण व सड़क से स्थाई अतिक्रमण को हटाने के लिए लोगों से बातचीत की। लोगों की सहमति के आधार पर सड़क को एक-रूपता के साथ निर्माण कराये जाने के लिए नगर आयुक्त ने सहायक अभियंता दानिश नकवी को अगले 3 दिनों में सड़क निर्माण कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के समय स्थानीय पार्षद असलम नूर ने जमालपुर नाले के दोनों साइड पर अवैध अतिक्रमण के कारण जाम लगने की समस्या से भी नगर आयुक्त को मौके पर अवगत कराया। नगर आयुक्त ने मौके पर ही नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त सपत्ति प्रभारी वीर सिंह को बुलाकर इस रोड की पैमाइश कराये जाने व अवैध अतिक्रमण को चिन्हित करने के लिए कहा।खैर रोड पर जल भराव की स्थिति देखने पहुंचे नगर आयुक्त को मौके पर 3 मोबाइल पंप पूरी क्षमता के



साथ चलते हुए मिले लेकिन चेतावनी के बावजूद नाले के ऊपर से अवैध रूप से रैप और स्लैब डालकर अतिक्रमण किए गए भवन स्वामी और दुकान स्वामियों द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाने की वजह से जल निकासी समुचित रूप से नहीं हो रही थी जिस पर नगर आयुक्त ने सख्त नाराजगी जताई। मौके पर सहायक नगर आयुक्त ने बताया कल सुबह 10:00 बजे इस तरह के अतिक्रमणों को चिन्हित कर लिया गया उन्हें हटाने की पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में कार्रवाई की जाएगी नगर आयुक्त ने कहा जल निकासी में बाधक अतिक्रमण किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे ऐसे भवन स्वामी और दुकानदारों से अपील की जाती है जल निकासी को प्रभावी बनाने के लिए नगर निगम का सहयोग करें नाले के ऊपर स्लैब और रैप को स्वयं हटाये।

ग्रीष्मावकाश के पश्चात जिलाधिकारी ने स्कूल चलो अभियान के तहत रोरी का तिलक लगाकर व पुष्प से बच्चों का किया स्वागत

बच्चों को प्रतिदिन स्कूल आने के लिए किया प्रेरित

मीरजापुर 01 जुलाई 2025- शैक्षिक सत्र 2025-26 में ग्रीष्मावकाश के पश्चात विद्यालय पुनः खुलने पर आज 01 जुलाई 2025 को जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन द्वारा गोद लिये पी0एम0 श्री कम्पोजिट विद्यालय कछवा मीरजापुर में स्कूल चलो अभियान के द्वितीय चरण के अन्तर्गत प्रातः 10:00 बजे उनके द्वारा स्वयं दो बच्चों आयुष पुत्र संजय व विनिश यादव पुत्र श्री राजेश यादव का कक्षा 1 में नामांकन किया गया। तत्पश्चात विद्यालय के नव प्रवेसित बच्चों को रोरी का तिलक लगाकर व पुष्प से स्वागत किया गया। बच्चों को अपने हाथों से पुस्तक, स्टेशनरी सामग्री एवं चॉकलेट्स का वितरण किया गया। बच्चे स्टेशनरी सामग्री व चॉकलेट पाकर आह्लादित हुए। जिलाधिकारी द्वारा बच्चो को प्रतिदिन विद्यालय आने के लिए प्रेरित किया गया। जिलाधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा स्कूल चलो अभियान के द्वितीय चरण में रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। स्कूल चलो अभियान की रैली नगर पंचायत कछवों के विभिन्न वार्डों में स्लोगन / नारे लगाते हुए रैली निकाला गया। जिलाधिकारी द्वारा उक्त विद्यालय में 1540 मीटर का मल्टीपरपज हॉल व उसके ऊपर 86 मीटर का 05 कमरों का निर्माण करवाने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात जिलाधिकारी द्वारा राजकीय बालिका इण्टर कालेज कछवा मीरजापुर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय विद्यालय परिसर में एक आडिटोरियम बनवाने हेतु अधिशासी अभियंता नगर पंचायत कछवा को निर्देशित किया गया।

नवाग्नतुक्त एसएसपी ने चार्ज लेते ही सुनी समस्याएं भारत संवाद

सहारनपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी ने कार्यवाह ग्रहण करते ही आज अपने कार्यालय में जनसुनवाई की और समस्याओं के समाधान के संबंधित थाना अध्यक्षों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।आज रिजर्व पुलिस लाइन स्थित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी द्वारा आमजन की विभिन्न शिकायतों को ध्यानपूर्वक सुना गया। जनसुनवाई के दौरान नागरिकों ने आपराधिक मामलों, भूमि विवाद, साइबर अपराध, पुलिस कार्यप्रणाली से जुड़ी समस्याओं समेत विभिन्न विषयों पर अपनी शिकायतें दर्ज कराईं। एसएसपी ने प्रत्येक फरियादी की बात को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित और प्रभावी कार्यवाही हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए। एसएसपी आशीष तिवारी ने कहा कि आमजन की समस्याओं का समयबद्ध और न्यायसंगत समाधान पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

फास्ट ट्रैक महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना समय की मां

भारत संवाद / योगेश शर्मा

अलीगढ़। मंगलायतन विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) इकाई-4 के तत्वावधान में महिला सशक्तिकरण विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाज में महिलाओं की भूमिका, चुनौतियों और उनके अधिकारों पर विस्तार से चर्चा की गई। कैसे महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर समाज में सशक्त भूमिका निभा सकें। वेबिनार में विद्यार्थियों, शिक्षकों व स्वयंसेवकों की सहभागिता रही।वेबिनार की मुख्य वक्ता डा. शीतल सिंह ने कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में काफी प्रयास हो रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत चिंता का विषय है। जब तक महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं होंगी, तब तक उनका सशक्तिकरण अधूरा रहेगा। समाज में महिलाओं को केवल घरेलू भूमिकाओं तक सीमित कर देना, उनके विकास में बड़ी बाधा है। उन्होंने बेटियों को शिक्षा और स्वरोजगार के अवसर देने की आवश्यकता पर बल दिया। संयोजक और एनएसएस इकाई की कार्यक्रम अधिकारी डा. निर्यति शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में महिलाओं को उनके अधिकारों और स्वतंत्रता के प्रति जागरूक करना था। एनएसएस समन्वयक डा. पूनम रानी ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से संदेश देना जरूरी है कि महिला सशक्तिकरण केवल एक नारा नहीं, बल्कि एक सामाजिक आवश्यकता है। कार्यक्रम में डा. शालू अग्रवाल, मनीषा उपाध्याय सहित छात्राओं अफीफा, कीर्ति, अन्नु, उर्वशी, खुशी आदि ने भी महिला सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार व्यक्त किए।

मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा संचारी रोग नियंत्रण अभियान जन जागरुकता रैली का हरी झंडी दिखाकर किया गया शुभारंभ

सुलतानपुर , जनपद में आज से प्रारंभ हो रहे संचारी रोग नियंत्रण अभियान (01 से 31 जुलाई 2025) का शुभारंभ मुख्य विकास अधिकारी अंकुर कौशिक द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रैली को रवाना कर किया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य संचारी रोगों जैसे डेंगू, मलेरिया, और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों को नियंत्रित करना और रोकथाम करना है। उक्त अभियान के तहत, स्वास्थ्य विभाग घर-घर जाकर लोगों को इन बीमारियों से बचाव के तरीकों के बारे में जागरूक करेगा और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा। अभियान के दौरान, लोगों को अपने घरों और आस-पास के वातावरण को साफ-सुथरा रखने, मच्छरों को पनपने से रोकने, और व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित किया जाएगा। यह अभियान 01 जुलाई से 31 जुलाई तक चलेगा।

डीएम ने किसानों को गुणवत्तायुक्त कीटनाशक उपलब्ध कराने के लिए टास्क फोर्स का किया गठन

प्रत्येक सप्ताह कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने के लिए निर्देश

अलीगढ़ (सू0वि0) :जिलाधिकारी संजीव रंजन द्वारा जिले में नकली कीटनाशक विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने, किसानों को गुणवत्तापूर्ण कीटनाशक उपलब्ध कराने एवं नियमित निगरानी और कार्रवाई के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि कृषकों को गुणवत्तायुक्त कीटनाशी रसायन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने, नकली, अमानक, अपंजीकृत व कीटनाशी अधिनियम 1968 के प्राविधानों का परिपालन कराने के लिए एउ कृषि निदेशक, जिला कृषि अधिकारी एवं जिला कृषि रक्षा अधिकारी की तीन सदस्यीय जिला स्तरीय स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो कि जिले की सभी तहसीलों में सघन निरीक्षण करेंगे।

विशेष रेलगाड़ियों के अतिरिक्त फेरों का संचालन

भारतीय रेल द्वारा अपने सम्मानित रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विशेष रेलगाड़ियों के संचालन अवधि में विस्तार का निर्णय लिया गया है। यह रेलगाड़ियों अपने पूर्व निर्धारित समय, ठहराव, संरचना एवं मार्ग पर चलेंगी, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

गाड़ी सं.	कहाँ से कहाँ तक	प्रस्थान का दिन	विस्तारित तिथि	
			से	तक
09117	उधना-सूबेदारगंज	शुक्रवार	04.07.2025	26.09.2025
*09118	सूबेदारगंज-उधना	शनिवार	05.07.2025	27.09.2025
*09075	मुम्बई सेन्ट्रल-काठगोदाम	बुधवार	02.07.2025	24.09.2025
*09076	काठगोदाम-मुम्बई सेन्ट्रल	गुरुवार	03.07.2025	25.09.2025
*09185	मुम्बई सेन्ट्रल-कानपुर अनवरगंज	रविवार	06.07.2025	28.09.2025
*09186	कानपुर अनवरगंज-मुम्बई सेन्ट्रल	सोमवार	07.07.2025	29.09.2025
*09039	उधना-धनबाद	शुक्रवार	04.07.2025	26.09.2025
*09040	धनबाद-उधना	रविवार	06.07.2025	28.09.2025
05045	लालकुआँ-राजकोट	रविवार	06.07.2025	31.08.2025
05046	राजकोट-लालकुआँ	सोमवार	07.07.2025	01.09.2025

महत्वपूर्ण सूचना:- *गाड़ी 09075 मुम्बई सेन्ट्रल से दिन बुधवार को दिनांक 20.08.2025, 27.08.2025 एवं 03.09.2025, *गाड़ी संख्या 09076 काठगोदाम से दिन गुरुवार को दिनांक 21.08.2025, 28.08.2025 एवं 04.09.2025, *गाड़ी संख्या 09185 मुम्बई सेन्ट्रल से दिन रविवार दिनांक 24.08.2025, 31.08.2025 एवं 07.09.2025 तथा *गाड़ी संख्या 09186 कानपुर अनवरगंज से दिन सोमवार को दिनांक 25.08.2025, 01.09.2025 एवं 08.09.2025 को नहीं चलेगी।

*गाड़ी संख्या 09118 सूबेदारगंज-उधना का ग्वालियर स्टेशन पर समय में संशोधन किया गया है। इस गाड़ी का आगमन/प्रस्थान 04.05/04.10 के स्थान पर 04.30/04.35 पर होगा।

***गाड़ी संख्या 09039/09040 उधना-धनबाद-उधना को उधना-गया-उधना के स्थान पर धनबाद तक विस्तारित किया गया है।**

संशोधित समय सारणी निम्नवत् है:-

गाड़ी सं. - 09039 उधना - धनबाद		गाड़ी सं. - 09040 धनबाद - उधना		
आगमन	प्रस्थान	स्टेशन	आगमन	प्रस्थान
----	22:00	उधना	09:40	----
16:00	16:02	मानिकपुर	13:00	13:02
19:50	20:00	प्रयागराज छिवकी	09:55	10:05
21:25	21:27	मिर्जापुर	08:20	08:22
08:00	----	धनबाद	----	23:50

नोट:- ट्रेनों से सम्बंधित जानकारी हेतु हेल्पलाइन 139 या Rail Madad Mobile App या वेबसाइट railmadad.indianrailways.gov.in का प्रयोग करें।

उत्तर मध्य रेलवे
©CPRONCR North central railways www.nccr.indianrailways.gov.in 1142/25(A)

बैठक समस्याओं के शीघ्र समाधान का दिया आश्वासन

विदेश व्यापार मंत्रालय भारत सरकार की अपर महानिदेशक सुश्री वृंदा मनोहर देसाई ने निर्यातकों के साथ की बैठक

भारत संवाद

अलीगढ़ 01 जुलाई 2025 (सू0वि0):- भारत सरकार विदेश व्यापार मंत्रालय की अपर महानिदेशक सुश्री वृंदा मनोहर देसाई ने मंगलवार को अलीगढ़ में प्रमुख निर्यातकों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं एवं आवश्यकताओं की जानकारी ली। बैठक में निर्यातकों द्वारा कच्चे माल (रॉ मैटेरियल) की दूर कम से कम तीन माह तक स्थिर रखने, निर्यात ऋण पर



व्याज अनुदान उपलब्ध कराने और क्लेम प्राप्ति की प्रक्रिया को सरल बनाने हुए न्यूनतम दस्तावेजीकरण सुनिश्चित

करने की मांग प्रमुखता से रखी गई। बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्यातकों के हित में संचालित

विभिन्न योजनाओं जैसे बाजार विपणन प्रोत्साहन योजना एवं गेटवे पोर्ट अनुदान योजना की भी विस्तृत जानकारी दी गई। जिला उद्योग केंद्र के सहायक प्रबंधक बृजेश यादव ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश निर्यात नीति-2025 तैयार की जा रही है, जिसके लिए प्रदेश भर के निर्यातकों से सुझाव प्राप्त किए जा चुके हैं। निर्यातकों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए सुश्री देसाई ने आवश्यकता के अनुसार समाधान

के लिए शीघ्र सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने स्थानीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिला निर्यात समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाएं और उनमें निर्यातकों द्वारा उठाए गए मुद्दों का त्वरित समाधान कराया जाए। यदि किसी विभाग द्वारा निर्यातकों को समस्याओं के निराकरण में लापरवाही बरती जाती है, तो इसकी सूचना सीधे उन्हें उपलब्ध कराई जाए।

भाषाविज्ञानी एवं मीडियाध्ययन विशेषज्ञ, 3-संरक्षक-भारत संवाद गजानन महतपुरकर, (सुपरिचित कवि, लेखक, गीतकार, मंच



क्या यूरिक एसिड में चना खा सकते हैं?

हाई यूरिक की समस्या समय के साथ बेहद गंभीर रूप लेनी लगती है। आपको ये जानकर हैरानी हो सकती कि जब शरीर में यूरिक एसिड बढ़ता है तो इसकी पथरियां आपकी किडनी में जमा होने लगती है। इसके अलावा ये शरीर के तमाम अंगों को भी प्रभावित करने लगता है जैसे कि ये हड्डियों के बीच पथरियों के रूप में जमा हो जाता है और सूजन का कारण बनने लगता है। ऐसे में कोशिश करनी चाहिए कि आप हाई प्रोटीन वाले फूड्स के सेवन से बचें। तो, ऐसे में सवाल ये है कि हाई यूरिक में चना खाएं या नहीं।

क्या हाई यूरिक में चना खा सकते हैं?

नहीं, अगर किसी को हाई यूरिक एसिड की समस्या है तो उसे चना, चने की दाल और चने की बनी तमाम चीजों को खाने से बचना चाहिए। ऐसा इसलिए कि चने में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है जिससे यूरिक एसिड की समस्या तेजी से बढ़ती है। इतना ही नहीं अगर किसी को पहले से ही हाई यूरिक एसिड की समस्या है तो चना खाना सूजन को ट्रिगर कर सकता है और दर्द का कारण बन सकता है। तो, इन तमाम कारणों से आपको हाई यूरिक एसिड में चना खाने से बचना चाहिए।

अगर खाएं तो कैसे खाएं?

अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो आपको चने को बिलकुल कम मात्रा में खाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इसे अंकुरित करके या फिर इस उबालकर खाएं। इस तरह से चने में फाइबर की मात्रा बढ़ती है जो कि पाचन क्रिया को इतना तेज कर देता है कि चने में मिलने वाला प्रोटीन पच जाता है। साथ ही ये मल में थोक जोड़ने का काम करता है जिससे पेट साफ होता है, प्यूरिन मल के साथ बाहर निकल जाता है और यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। तो, पहले तो चना खाने से परहेज करें और अगर आप खा भी रहे हैं तो इन बातों का ख्याल रखें। ऐसे करना आपको यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। इसकी जगह आप मूंग जैसी दाल का सेवन कर सकते हैं।

चुकंदर से बनाएं फेशियल से मिलेगी ग्लास स्किन, 10 मिनट में मिलेगा पार्लर जैसा निखार

अगर आप भी चुकंदर फेशियल का इस्तेमाल करती हैं, तो आपकी स्किन भी ग्लास की तरह चमकने लगेगी। इससे स्किन पर ऐसा अद्भुत निखार आता है कि हर कोई आपसे आपकी चमकदार स्किन का राज पूछेगा। आज हम आपको जादुई चुकंदर फेशियल के स्टेप्स के बारे में बताने जा रहे हैं।

आज के समय में हर महिला ग्लास स्किन पाना चाहती है। ऐसी स्किन जो इतनी साफ और निखरी हो कि शीशे की तरह चमके। इस तरह का निखार पाने के लिए महिलाएं अक्सर महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन आप किचन में मौजूद एक चीज से अच्छे रिजल्ट पा सकती हैं। वो भी सिर्फ 20 रुपए में। बता दें कि चुकंदर सिर्फ स्वास्थ्य के लिए ही नहीं बल्कि स्किन के लिए भी अच्छा माना जाता है। चुकंदर में एंटी ऑक्सीडेंट, विटामिन सी और कई मिनरल्स पाए जाते हैं। जो स्किन को गहराई से पोषण

देने का काम करते हैं।

ऐसे में अगर आप भी चुकंदर फेशियल का इस्तेमाल करती हैं, तो आपकी स्किन भी ग्लास की तरह चमकने लगेगी। इससे स्किन पर ऐसा अद्भुत निखार आता है कि हर कोई आपसे आपकी चमकदार स्किन का राज पूछेगा। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको जादुई चुकंदर फेशियल के स्टेप्स के बारे में बताने जा रहे हैं।

फेस क्लीजिंग

फेशियल का सबसे पहला और जरूरी स्टेप स्किन की गहरानी से सफाई करना है। इससे स्किन की धूल-मिट्टी और ऑयल को दूर किया जा सकता है। वहीं चुकंदर का रस नेचुरल क्लीजर की तरह काम करता है। जोकि स्किन के पोर्स साफ करता है और विटामिन देता है। गुलाब जल स्किन को शांत करने के साथ ही नमी देने का काम करता है और स्किन के पीएच बैलेंस को बनाए रखता है।

सामग्री

चुकंदर का जूस- 2 चम्मच
गुलाब जल- 2 चम्मच
विधि

चुकंदर के रस में गुलाबजल मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लें।

इसके बाद कॉटन को भिगोकर फेस और गर्दन को अच्छे से साफ कर लें।

ऐसा करने से सारी गंदगी साफ हो जाएगी और ऑयल भी साफ होगा। इससे आपकी तरोताजा लगेगी।

फेस स्क्रब

बता दें कि क्लीजिंग के बाद स्किन को एक्सफोलिएट करना बेहद जरूरी होता है। जिससे कि डेड स्किन सेल्स हट जाएं और आपकी स्किन खुलकर सांस ले सके। इससे ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स की समस्या दूर होती है। वहीं कॉफी नेचुरल एक्सफोलिएट है, जोकि डेड स्किन को हटाने,

स्किन को स्मूथ बनाने और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में मदद करता है। चुकंदर का रस स्किन को पोषण और ग्लो देने का काम करता है।

सामग्री

चुकंदर का जूस- 2 चम्मच
कॉफी पाउडर- 2 चुटकी
विधि

चुकंदर के जूस में कॉफी पाउडर मिलाकर इसको अच्छे से मिक्स करके दरदरा पेस्ट बनाएं।

अब इस स्क्रब को फेस और गर्दन पर लगाएं और उंगलियों में पोरों से हल्के हाथों से फेस पर 2-3 मिनट के लिए मसाज करें।

कुछ देर मसाज करने के बाद फेस को गुनगुने पानी से धो लें।

इससे आपका चेहरा पहले से ज्यादा साफ और चमकदार नजर आएगा।

स्किन लाइटनिंग जेल

स्क्रबिंग के बाद स्किन को शांत करने और नमी देना जरूरी होता है। स्किन लाइटनिंग जेल आपकी त्वचा को ठंडक पहुंचाने के साथ चमकदार बनाने का काम करता है। एलोवेरा जेल हाइड्रेटिंग, सुईंग और हीलिंग गुणों के लिए जाना जाता है। एलोवेरा स्किन की जलन को कम करता है, नमी को लॉक करता है और स्किन को सॉफ्ट बनाता है। एलोवेरा को चुकंदर के साथ मिलाकर लगाने से स्किन की रंगत में सुधार होता है और ग्लो आता है।

सामग्री

चुकंदर का जूस- 2 चम्मच
एलोवेरा जेल- 2 चम्मच

विधि

सबसे पहले चुकंदर के रस में एलोवेरा जूस को अच्छे से मिक्स करें।

अब फेस को साफ करके 5 मिनट मसाज करें। इसके बाद चेहरे को धो लें।

फेस पैक

फेशियल का लास्ट स्टेप फेस पैक होता है, जो आपकी स्किन को टाइट करने का काम करता है। स्किन को पोषण देता है और परमानेंट ग्लो देता है। इस फेस पैक में मौजूद बेसन आपकी स्किन की गहराई से सफाई करता है और एक्स्ट्रा ऑयल को सोखता है और स्किन की रंगत को निखारने का काम करता है। वहीं गेहूं का आटा स्किन को एक्सफोलिएट करने के साथ टैनिंग को रिमूव करने में भी मदद करता है। साथ ही चुकंदर का रस इस फेस पैक को एंटी ऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर बनाने का काम करता है।

सामग्री

चुकंदर का जूस- 2 चम्मच
आटा- 1 चम्मच
बेसन- 1 चम्मच

विधि

सबसे पहले बेसन में आटा और चुकंदर का जूस मिलाकर फेस पैक बनाएं।

अब इसको लाइटनिंग फेस पैक को फेस और गर्दन पर अर्पण करें।

फिर 20 मिनट बाद फेस वॉश कर लें।

चुकंदर फेशियल के सभी स्टेप्स को पूरा करने के बाद आप पाएंगे कि आपकी स्किन में पॉजिटिव बदलाव आए हैं। इससे न सिर्फ आपकी स्किन साफ और तरोताजा बनेगी, बल्कि सॉफ्ट और शाइनी बन जाएगी। ठीक वैसे जैसे ग्लास स्किन होती है। इस फेशियल को सप्ताह में एक बार इस्तेमाल करने से आपकी स्किन की रंगत में सुधार होता है, स्पोर्ट्स आदि कम होते हैं और बिना किसी खर्च के आपको शीशे जैसी चमकती स्किन मिलेगी।

घर पर बना रहे हैं पंजाबी दाल तड़का, ये टिप्स आएंगे आपके बेहद काम

जब आप पंजाबी दाल तड़का बना रही हैं तो ऐसे में सिर्फ एक ही दाल का इस्तेमाल करने से बचें। इसकी जगह आप एक हिस्सा अरहर की दाल, एक हिस्सा मसूर और थोड़ा सा मूंग डालें। जब आप ऐसा करती हैं तो इससे दाल में एकदम बढ़िया क्रीमी और टेस्टी बनती है।

जब कुछ हल्का लेकिन टेस्टी खाने का मन होता है तो हम अक्सर दाल खाना पसंद करते हैं। अमूमन दाल को घर-घर में अलग तरीकों से बनाया जाता है। लेकिन अगर आपको चटपटा खाना पसंद आता है तो ऐसे में आप पंजाबी दाल तड़का बनाकर उसका स्वाद चख सकते हैं। पंजाबी दाल तड़का में लहसुन की खुशबू और ऊपर से लगाया हुआ तड़का आपको स्वाद की एक अलग दुनिया में लेकर आता है। आप दाल तड़का को चावल के साथ या फिर तंदूरी रोटी के साथ खा सकते हैं।

लेकिन अक्सर यह देखा जाता है कि हर बार दाल वैसी नहीं बनती। कभी ज्यादा पानीदार हो जाती है तो कभी इसका स्वाद उतना अच्छा नहीं आता है। ऐसे में जरूरी है कि आप पंजाबी दाल तड़का बनाते हुए कुछ छोटे-छोटे टिप्स को फॉलो करें। इन टिप्स की मदद से आपकी दाल एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बनती है और हर किसी को वह खाने में बेहद ही अच्छी लगती है। तो चलिए आज इस लेख में हम आपको पंजाबी दाल तड़का बनाते समय फॉलो किए जाने वाले कुछ आसान टिप्स के बारे में बता रहे हैं-

अलग-अलग दालों का करें इस्तेमाल



जब आप पंजाबी दाल तड़का बना रही हैं तो ऐसे में सिर्फ एक ही दाल का इस्तेमाल करने से बचें। इसकी जगह आप एक हिस्सा अरहर की दाल, एक हिस्सा मसूर और थोड़ा सा मूंग डालें। जब आप ऐसा करती हैं तो इससे दाल में एकदम बढ़िया क्रीमी और टेस्टी बनती है।

दाल को आधे घंटे भिगोएं

दाल को कभी भी सीधे ही उबालने के लिए नहीं रखना चाहिए। इसकी जगह आप इसे कम से कम 30 मिनट भिगो कर रखें। इससे दाल जल्दी पकती है, बराबर पकती है और पाचन भी आसान होता है। ये रेस्टोरेंट वाली स्मूथ दाल की टेक्सचर का राज है।

दाल को अच्छी तरह पकाएं

जब आप पंजाबी दाल तड़का बना रही हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि यह पूरी तरह नरम होनी चाहिए, दानेदार नहीं। इसके लिए दाल में कम से कम 3-4 सीटी लगाओ, फिर अच्छी तरह मैश करो। मैश करने से दाल चिकनी और क्रीमी बनती है, जो रोटी या चावल के साथ खाने में काफी अच्छी लगती है।

तड़के का रखें ख्याल

पंजाबी दाल तड़का का असली स्वाद उसके तड़के में छिपा होता है, इसलिए आप उसके साथ किसी तरह का समझौता ना करें। तड़के के लिए देसी घी का इस्तेमाल करें। सबसे पहले उसे अच्छे से गरम करो, फिर जीरा, हींग, लहसुन और प्याज डालो। गरम घी में जीरा और लहसुन का पूरा स्वाद आता है और उसकी खुशबू निकलती है। अब आप इसे उठे घी में डालोगे तो वो क्रैकलिंग नहीं करेगा और फलेवर भी नहीं आएगा।

थाइलैंड में कोर्ट ने पीएम को पद से हटाया

कंबोडिया के नेता से बात करते हुए आर्मी चीफ की आलोचना की थी; अब डिप्टी पीएम पद संभालेंगे

एजेंसी

बैंकॉक, थाईलैंड के संवैधानिक न्यायालय ने पीएम पाइतोंग्तान शिनावत्रा को उनके पद से सस्पेंड कर दिया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने कंबोडिया के नेता हुन सेन से फोन पर बातचीत की थी। इस बातचीत में उन्होंने थाई सेना के कमांडर की आलोचना की थी। इसे थाईलैंड में गंभीर मामला माना जाता है क्योंकि सेना का वहां काफी प्रभाव है। इस बातचीत के लीक होने के बाद देशभर में गुस्सा फैल गया

था। कोर्ट ने 7-2 के अंतर से पीएम को पद से हटाया। कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ शिकायत की जांच की जाएगी। अगर वह दोषी पाई गई तो उन्हें हमेशा के लिए पद से हटाया जा सकता है। पीएम ने खिलाफ नैतिकता के उल्लंघन का मामला स्वीकार कर लिया है और अब जांच पूरी होने तक वह प्रधानमंत्री के पद पर काम नहीं कर सकेंगी। जब तक इस मामले पर अंतिम फैसला नहीं होता, तब तक डिप्टी पीएम फुमथम वेचायाचाई सरकार चलाएंगे। सहयोगी पार्टी ने साथ छोड़ा,



अब सरकार पर संकट इस कॉल के

लीक होने से सरकार पर भारी दबाव

बना हुआ है। एक बड़ी पार्टी गठबंधन छोड़ चुकी है, जिससे गठबंधन बहुमत कमजोर हो गया है। पाइतोंग्तान ने माफी मांगते हुए कहा है कि उनकी टिप्पणी सिर्फ विवाद सुलझाने के लिए थी। पाइतोंग्तान ने कहा है कि वह कोर्ट की प्रक्रिया का सम्मान करेंगी और उसे मानेंगी, लेकिन उन्होंने यह भी माना कि वह चिंतित हैं। इस बीच पाइतोंग्तान के खिलाफ भ्रष्टाचार आयोग भी जांच कर रहा है, जिससे उन पर पद से हटाए जाने का खतरा और बढ़ गया है। वहीं, थाई राजा ने उनके मंत्रिमंडल में बदलाव

को मंजूरी दी है। नए फेरबदल में कुछ पुराने मंत्रियों को हटाकर नए लोगों को शामिल किया गया है। इस बीच पाइतोंग्तान ने खुद को संस्कृति मंत्री बना लिया है। उन्होंने कहा कि वह थाई संस्कृति को दुनिया भर में पहचान दिलाने पर काम करेंगी। थाईलैंड और कंबोडिया दुनिया के सबसे अच्छे पड़ोसी देशों में से माने जाते थे। कुछ साल पहले तक दोनों देशों के नेताओं का मानना था कि उनकी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी, क्योंकि वे एक लंबी सीमा साझा करते हैं और मिलकर आगे

बढ़ना उनके लिए जरूरी है। लेकिन हाल के समय में हालात बदल गए और उनके बीच तनाव काफी बढ़ गया है। 28 मई को सीमा पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच भिड़ंत हुई, जिसमें एक कंबोडियाई सैनिक की मौत हो गई थी। यह वो जगह है थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस की सीमाएं मिलती हैं। थाईलैंड और कंबोडिया दोनों ही इस इलाके पर दावा करते हैं। सैनिक की मौत से नाराज होकर कंबोडिया के नेता हुन सेन ने सीमा पर और सैनिक और हथियार भेजने का आदेश दिया, उन्होंने

कहा कि वे युद्ध नहीं चाहते, लेकिन हमला होने पर जवाब देना पड़ेगा। थाई पीएम ने इसके जवाब में कहा कि थाईलैंड ऐसी किसी धमकी को बर्दाश्त नहीं करेगा।

इसके बाद कंबोडिया ने धमकी दी कि वह इस विवाद को अंतरराष्ट्रीय अदालत में ले जाएगा, लेकिन थाईलैंड ने यह कहकर इनकार कर दिया कि वह अदालत के अधिकार को नहीं मानता। इसके बाद थाईलैंड ने कंबोडिया की बिजली और इंटरनेट सेवा रोकने की धमकी दी, तो कंबोडिया ने थाई टीवी और फिल्मों पर बैन लगा दिया और थाई प्रोडक्ट्स के आयात पर रोक लगा दी।

तुर्किये में पैगंबर मोहम्मद के कथित कार्टून पर विवाद

मिसाइलों की बारिश के बीच मूसा से हाथ मिलाते दिखे, कार्टूनिस्ट समेत 4 गिरफ्तार

एजेंसी

अंकारा, तुर्किये में पैगंबर मोहम्मद का कार्टून छपने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक, लैमैन मैगजीन ने 26 जून को एक कार्टून पब्लिश किया था, जिसमें पैगंबर मोहम्मद और पैगंबर मूसा जैसे दिखने वाले दो शख्स को आसमान से गिरती मिसाइलों के बीच हवा में हाथ मिलाते हुए दिखाया गया था। इस कार्टून के सामने आने के बाद पूरे तुर्किये में लोगों का गुस्सा भड़क गया। गुस्साए लोगों ने इस्तांबुल में लैमैन मैगजीन के ऑफिस के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वे दांत के बदले



दांत, खून के बदला खून के नारे लगा रहे थे। कुछ प्रदर्शनकारियों ने, जो एक

इस्लामिक संगठन से जुड़े बताए जा रहे हैं, पत्रिका के दफ्तर पर पत्थरबाजी

भी की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कार्टून बनाने वाले कार्टूनिस्ट डोगन पहलवान को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा लैमैन के चीफ एडिटर, मैनेजिंग एडिटर और ग्राफिक डिजाइनर की भी गिरफ्तारी हुई है। घटना के बाद तुर्किये के गृहमंत्री अली येरलिकाया ने बयान जारी कर कहा कि यह प्रेस की आजादी या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि धार्मिक भावनाओं का अपमान है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तुर्किये के न्याय मंत्री विलमाज टुंक ने कहा कि इस तरह के कार्टून धार्मिक भावनाओं और सामाजिक सौहार्द का अपमान करते हैं। उन्होंने सोशल

मीडिया पर लिखा कि कोई भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बहाना बनाकर किसी धर्म के प्रतीकों का अपमान नहीं कर सकता। गृह मंत्री येरलिकाया ने कहा कि वे पैगंबर साहब का मजाक उड़ाने वाले इस शर्मनाक कार्टून को निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की हरकतें हमारे धार्मिक भावनाओं का अपमान करती हैं। मुसलमानों के दिल को ठेस पहुंचाती हैं। ये काम लोगों को भड़काने वाले हैं और जो ऐसा करने की कोशिश करेंगे, उन्हें कानून के सामने जवाब देना होगा। उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें कार्टूनिस्ट को हथकड़ी लगाकर सीढ़ियों पर ले जाया जा रहा है।

ट्रम्प बोले-सब्सिडी बंद की तो मस्क को अफ्रीका लौटना पड़ेगा

दुकान बंद हो जाएगी, फिर न कार बनेगी, न सैटेलाइट लॉन्च होंगे

एजेंसी

वॉशिंगटन डीसी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने मंगलवार को टेक्सा के सीईओ इलॉन मस्क पर तंज कसा। उन्होंने कहा- अगर मस्क को मिलने वाली सब्सिडी बंद हो जाए, तो उनको अपनी दुकान (कंपनी) बंद करके दक्षिण अफ्रीका लौटना पड़ेगा। ट्रम्प के कहा कि सब्सिडी बंद होने से न तो टेस्ला इलेक्ट्रिक कार का प्रोडक्शन कर पाएगी, न ही स्पेसएक्स के रॉकेट, सैटेलाइट लॉन्च होंगे। ट्रम्प ने दावा किया कि मस्क को सरकारी सब्सिडी के तौर पर इतना पैसा मिला है, जितना शायद किसी और को नहीं मिला। उन्होंने सुझाव दिया कि डीओआई इस मामले को डिटेल् जांच करे। इससे देश का पैसा बचेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा- मस्क को राष्ट्रपति पद के लिए मेरा समर्थन करने से बहुत पहले ही पता था कि मैं ई.वी.मैडेट के खिलाफ हूँ। इलेक्ट्रिक गाड़ियां अच्छी हैं, लेकिन हर इंसान को इन्हें खरीदने के लिए मजबूर करना गलत है। दरअसल, इलॉन मस्क ने शनिवार को ट्रम्प के बिग ब्यूटीफुल बिल की एक बार फिर से आलोचना की थी। मस्क ने शनिवार को एक्स पर लिखा था- ट्रम्प का यह बिल अमेरिका में लाखों नौकरियां खत्म कर देगा और हमारे देश को बहुत बड़ा रणनीतिक नुकसान पहुंचाएगा। मस्क ने कहा, यह पूरी तरह पागलपन से भरा और विनाशकारी है। यह कानून



पुराने उद्योगों को रियायत देता है, लेकिन भविष्य के उद्योगों को तबाह कर देगा। मस्क ने पिछले महीने इस बिल को लेकर ट्रम्प प्रशासन में गवर्नमेंट एफिशिएंसी विभाग के प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया था। अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बिग ब्यूटीफुल बिल को चर्चा के लिए मंजूरी दे दी है। शनिवार देरा त हुई वोटिंग में सीनेट ने 51-49 वोटों के अंतर से एक प्रस्ताव पारित किया, जिससे सदन को बिल पर बहस शुरू करने की इजाजत मिल गई।

दो रिपब्लिकन सीनेटरों ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया। वोटिंग के दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस मौजूद थे क्योंकि टाई की स्थिति में उनके वोट करने की जरूरत पड़ सकती थी। ट्रम्प टैक्स और खर्च में कटौती करने वाले इस बिल को 4 जुलाई से पहले पारित कराना चाहते हैं। ट्रम्प और मस्क दो महीने पहले बिग ब्यूटीफुल बिल को

लेकर आमने-सामने आ गए थे। ट्रम्प इस बिल के समर्थन में हैं, जबकि मस्क खिलाफ। ट्रम्प का दावा है कि यह देशभक्ति से भरा हुआ कानून है। इसके पारित होने से अमेरिका में निवेश बढ़ेगा और चीन पर निर्भरता घटेगी। जबकि मस्क इसे पोर्क फिल्ड यानी कि बेकार खर्चों से भरा बिल मानते हैं। ट्रम्प और मस्क के बीच 5 जून को बिग ब्यूटीफुल बिल को लेकर बहस तब शुरू हुई जब ट्रम्प ने मीडिया से बात करते हुए मस्क को लेकर नाराजगी जताई थी। ट्रम्प ने कहा था कि जब हमने अनिवार्य तौर पर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के कानून में कटौती करने की बात कही तो मस्क को दिक्कत होने लगी। मैं इलांन से बहुत निराश हूँ। मैंने उनकी बहुत मदद की है।

इसके बाद मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रम्प को एहसान फरमाइश बताते हुए लगातार कई ट्वीट किए।

हिंदू युवती से दुष्कर्म मामले में बांग्लादेश में विरोध तेज

आरोपियों ने रेप का वीडियो बनाकर वायरल किया; पुलिस ने एक्सट्रामैरिटल अफेयर बताने की कोशिश की

एजेंसी

ढाका, कुमिल्ला के मुरादनगर में 26 जून 2025 को 21 वर्षीय हिंदू युवती के साथ हुई दुष्कर्म की घटना को लेकर देशभर में प्रदर्शन और सियासत तेज हो गई है। एक ओर जहां हिंदू संगठनों और मानवाधिकार संगठनों ने देशभर के कई शहरों में उग्र प्रदर्शन किया। उधर, राजनीतिक दलों में इस घटना पर विवाद छिड़ गया। पूर्व पीएम शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग और पूर्व पीएम खालिदा जिया की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट



पार्टी (बीएनपी) ने आरोपी फजोर अली को एक-

दूसरे का नेता बताकर आरोप लगाए। जमात-ए-इस्लामी ने भी इस मामले में बीएनपी को निशाना बनाया। पहले बांग्लादेश पुलिस और यूनुस समर्थकों ने इस मामले को एक्सट्रामैरिटल अफेयर बताने की कोशिश की। वहीं, कुमिल्ला के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एकेएम कमरुज्जमां ने जांच में इसे क्रूर यातना का मामला बताया। उन्होंने कहा कि पीड़ित सरल स्वभाव की है और एक्सट्रामैरिटल अफेयर का कोई सबूत नहीं मिला। इसके बाद अल्पसंख्यक समुदाय में गुस्सा फैल गया। ढाका यूनिवर्सिटी के छात्रों ने रात में विरोध

मार्च निकाला। सात जिलों में हिंदू समुदाय ने मानव श्रृंखला बनाकर न्याय की मांग की। हाईकोर्ट ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए पीड़ित की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया। जस्टिस फहमिद कादर और जस्टिस सैयद जाहिद मंसूर की बेंच ने रविवार को एक रिट याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद यह निर्देश जारी किया। कोर्ट ने सभी सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पीड़ित के वीडियो और तस्वीरें 24 घंटे के भीतर हटाने का आदेश दिया। पीड़ित को चिकित्सा और सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कर्मचारियों के लिए आरक्षण नीति लागू की, पदोन्नति में भी मिलेगा लाभ

यह नीति 23 जून 2025 से प्रभावी हुई है और इसमें रजिस्ट्रार, वरिष्ठ निजी सहायक, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष जैसे पद शामिल हैं.



एजेंसी

नई दिल्ली: भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कर्मचारियों के लिए पहली बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों को सीधी नियुक्ति और पदोन्नति में आरक्षण देने की नीति को औपचारिक रूप से लागू कर दिया है. इस निर्णय को न्यायालय के प्रशासनिक ढांचे में सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. यह नीति न्यायाधीशों पर लागू नहीं होगी. किन पदों पर लागू होगी नीति नई आरक्षण नीति रजिस्ट्रार, वरिष्ठ निजी सहायक, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष, कनिष्ठ न्यायालय सहायक, और चैंबर अटेंडेंट जैसे प्रशासनिक और सहायक पदों पर लागू होगी. इससे इन वर्गों के कर्मचारियों को पदोन्नति और नियुक्ति में आरक्षित अवसर मिल सकेंगे परिपत्र में आगे कहा गया है, यदि किसी कर्मचारी को रोस्टर या रजिस्ट्रार में कोई त्रुटि दिखाई दे, तो वे रजिस्ट्रार (भर्ती) को आपर्ति/प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. यह आरक्षण न केवल नई नियुक्तियों, बल्कि पदोन्नति में भी लागू किया

24 जून को जारी हुआ परिपत्र
सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारियों को 24 जून को जारी एक परिपत्र के माध्यम से यह जानकारी दी गई. इसमें कहा गया कि मॉडल आरक्षण रोस्टर और संबंधित रजिस्ट्रार को सुप्रीम कोर्ट के आंतरिक नेटवर्क 'सुपेनेट' पर अपलोड कर दिया गया है, और यह नीति 23 जून 2025 से प्रभावी मानी जाएगी. मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई के कार्यकाल में आया निर्णय यह ऐतिहासिक निर्णय उस समय आया है जब भारत के मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई सर्वोच्च न्यायालय का नेतृत्व कर रहे हैं. वे अनुसूचित जाति समुदाय से आने वाले देश के दूसरे मुख्य न्यायाधीश हैं. उनके कार्यकाल में आया यह बदलाव न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व और समावेशिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है. समावेशी न्यायपालिका की दिशा में कदम यह नीति सुप्रीम कोर्ट के भीतर विविधता और समान अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है. लंबे समय से चली आ रही मांगों और बहसों के बीच यह फैसला न्यायपालिका के प्रशासनिक ढांचे को अधिक प्रतिनिधित्वशील और उत्तरदायी बनाने की कोशिश है.

राजस्थान के अलवर में सड़के ढूँबीं, घरों में पानी:हिमाचल में 11 जगह बादल फटा, 5 की मौत

उत्तराखंड में सोमवार को कोटद्वार-बद्रीनाथ मार्ग पर सतपुली के पास लैंडस्लाइड की वजह से पौड़ी-मेरठ नेशनल हाईवे बंद हो गया। उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड के कारण यमुनोत्री हाईवे बंद हो गया है। देशभर में बारिश से जुड़े अपडेट्स के लिए नीचे दिए ब्लॉग से गुजर राजस्थान के अलवर में बाढ़ जैसे हालात, महिला थाने, अस्पताल में पानी भराराजस्थान के अलवर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं।

एजेंसी

नई दिल्ली, देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसूनी बारिश जारी है। राजस्थान के अलवर में सोमवार को भारी बारिश के चलते सड़कों पर दो फीट तक पानी भर गया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा-यमुना में बाढ़ जैसे हालात हैं। घाट की तरफ 500 मीटर आगे तक पानी भर गया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में पिछले 24 घंटे में 11 जगह बादल फटा। बाढ़ और लैंडस्लाइड से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, 16

16 लापता; प्रयागराज में गंगा-यमुना में बाढ़



लोग लापता हैं। उत्तराखंड में सोमवार को कोटद्वार-बद्रीनाथ मार्ग पर सतपुली के पास लैंडस्लाइड की वजह से पौड़ी-मेरठ नेशनल हाईवे बंद हो गया। उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड के कारण यमुनोत्री हाईवे बंद हो गया है। देशभर में बारिश से जुड़े अपडेट्स के लिए नीचे दिए ब्लॉग से गुजर राजस्थान के अलवर में बाढ़ जैसे हालात,

महिला थाने, अस्पताल में पानी भराराजस्थान के अलवर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। सुबह 7 से 8 बजे के बीच हुई तेज बरसात के बाद सड़कों पर पानी भर गया। दर्जनों गाड़ियां फंस गईं। यहां महिला थाने से लेकर हॉस्पिटल तक में कई फीट पानी भर गया। गायत्री मंदिर रोड पर गायत्री कॉलोनी, एसपी

उत्तराखंड में भी कांवड़ रूट पर लिखना होगा दुकानों पर नाम, वरना लगेगा दो लाख का जुर्माना, शासन का आदेश

स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान पंडालों, भंडारों और अन्य भोजन केंद्रों पर परोसे जा रहे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. मिलावट खोरों और मानकों से खिलवाड़ करने वाली के विरुद्ध तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यात्रियों की सेहत हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की विशेष टीमें हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, पौड़ी और उत्तरकाशी जिलों में तैनात की गई हैं.

एजेंसी

देहरादून: यूपी के बाद उत्तराखंड में भी कांवड़ यात्रा के दौरान रेहड़ी-पटरी, ढाबा और अन्य दुकानदारों को फोटो

के साथ पहचान पत्र व फुड लाइसेंस साफ-साफ लिखकर लगाना होगा. इसको लेकर खाद्य सुरक्षा एवं औषधी प्रशासन की तरफ से आदेश भी जारी किया गया है. बता दें कि आगामी 11 जुलाई से कांवड़ मेला शुरू होने जा रहा है. कांवड़ मेले के दौरान श्रद्धालुओं को शुद्ध और साफ सुथरा भोजन मिले, इसके लिए स्वास्थ्य सचिव और आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन आर राजेश कुमार की तरफ से कुछ दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है.जारी



दिशा निर्देश के अनुसार हर खाद्य कारोबारी को अपने लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र की एक साफ-

सुथरी प्रति अपने दुकान में ऐसी जगह पर लगानी होगी, जिसे उपभोक्ता आसानी से देख और पढ़ सकें. छोटे

व्यापारियों व ठेले-फड़ वालों को भी अपना फोटो पहचान पत्र और पंजीकरण प्रमाण पत्र अपने पास रखना और दिखाना जरूरी होगा.होटल, भोजनालय, ढाबा और रेस्टोरेंट में 'फूड सेफ्टी डिस्ट्रिब्यूट बोर्ड' भी साफ-साफ दिखाई देने वाले स्थान पर लगाया जाना चाहिए, जिससे ग्राहक को यह पता चल सके कि खाने की गुणवत्ता की जिम्मेदारी किसकी है. जो कारोबारी ये निर्देश नहीं मानेंगे, उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 55 के तहत कार्रवाई की जाएगी,

जिसमें 2 लाख रुपए तक का जुमाना लग सकता है. सभी संबंधित अधिकारी इन आदेशों का कड़ाई से पालन कराएंगे. श्रद्धालुओं की सेहत के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा.स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान पंडालों, भंडारों और अन्य भोजन केंद्रों पर परोसे जा रहे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. मिलावट खोरों और मानकों से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी. यात्रियों की सेहत हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है.

